श्रम विभाग दिनांक 18 दिसम्बर, 1985 a

सं श्रो वि /एफ डी । / 274-85 / 51056. — चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं । प्राम्पट फोर्राजग प्रा । लिं । ए-7 ई. एल एक, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, फरीताबाद, के श्रीमक श्री दयानन्द यादव तथा उसके प्रवन्धकों के मुम्बद् इसके बाद लिखित मामलें में कोई श्रोदोगिक विवाद है ;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निविष्ट करैना बांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा शरकारी श्रीधस्चना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ेंते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त श्रिधिनयम की धारा 7 के श्रीशिन गठित श्रभ न्यायालय, फरीराबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत श्रथवाद संबंधित मामला है:—

क्या श्री द्यानन्द यादन की सेवाओं का समापन न्यायोजित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का •हकदार है ?

- दिनांक 20 दिसम्बर, 1985 सं ग्रो० वि०/एफ बी०/35-85/51470. - चूंकि हरियाणा के राज्येपाल की राय है कि मैं० स्टेरी वेयर प्रा० लि० प्लाट नं । 16, संकटर 24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री दिनेश्वर पाण्डे तथा उसके प्रत्यकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव, श्रीद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिवतियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी श्रिधिस्चना सं० 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़तें हुए श्रिधि चना सं० 11495-जी श्रम 57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उवत श्र्धिनियम की धारा 7 के श्रधीन गठित श्रम न्यायात्रय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत यी उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने ितृ निर्दिष्ट करते हैं जो कि उकत प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद स्से सुसंगत श्रथवा सम्बन्धित गामला है :--

क्या श्री दिनेश्वर पाण्डे की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किह राहुत का हकदार है ?

सं ग्रो॰ वि॰/रोहतक/51476. चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं॰ जिला शिक्षा ग्रधिकारी रोहतक, के श्रमिक श्री राम फल, तथा, उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित माम्ले में कोई ग्रीचोगिक विवाद है;

श्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को त्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना , सं० 9641-1-अम-78/32573, दिनांक 8 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधिन गठित अम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित जीचे लिखा मामला न्यायनिगय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उनत प्रवन्धकों तथा अभिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उनत विवाद से सुसंगत अधुवा सम्बन्धित मामला है :---

क्या श्री राम फल की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किसे राहत का हकदार है ? संव श्रोव विव/रोहतक/51483.—चूंकि हरियाणा के राज्यवाल की राय है कि मैंव जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक, के श्रीमिक श्री मंगत राम, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चूंकि हरियाणा के राज्यवाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना खांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम्, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिमूचना सं० 9641-1-अम/78/32573, दिनांक 8 नवम्बर, ० 1970, के साथ गठित सरकारी अधिमूचना की धारा 7 के अधीन गठित अपन न्यायालय, रोहतक, को विवाद प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उनत प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विद्याद प्रस्त मामला है या उन्त विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है :---

ू वया श्री मंगत राम की सेवाओं का समापन न्यायोजित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?